NYAYA SADAN

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA), Near A.G. Office, Doranda,
Ranchi- 834002
Phone: 0651-2481520 (O), 2482392, Fax: 2482397, E-mail – jhalsaranchi@gmail.com

PATRON-IN-CHIEF
Hon'ble Chief Justice
Jharkhand High Court

EXECUTIVE CHAIRMAN
Justice D. N. Patel
Judge
Jharkhand High Court

MEMBER SECRETARY
Arun Kumar Rai
(Principal District Judge)

Ref No: JHALSA/1697
Dated: 18/8/18

To,

All the Principal District Judges-cum-Chairmen
District Legal Services Authorities-including Judicial Commissioner-cum-Chairman, District Legal Services Authority, Ranchi

Sub.: Directions of His Lordship Hon'ble Executive Chairman, JHALSA on Jail PLVs, Video Conferencing and Legal Services Hand bill.

Sir,

It is conveyed that His Lordship Hon'ble Executive Chairman, JHALSA has been pleased to issue certain **directions/guidelines for ensuing effective access to justice to the poor** and downtrodden sections of the society. The said directions are reproduced as under:

1. *The DLSAs should strictly ensure payment of remuneration to Jail PLVs by 5th of the month positively. If funds are insufficient, the allotment is required to be sought from JHALSA well in advance.*

2. *The Member Secretary, JHALSA to hold Video Conferencing with Secretaries,DLSA, Remand Advocates, Retainer Lawyers, Panel Advocatec, once in every quarter, either jointly or separately. The said VC would target on effective implementation of NALSA Schemes, Timely payment of bills of PLVs and Panel Advocates, Effective outreach methods and related legal services topics.* ***First Video Conference is scheduled on 28th Aug 2018 at 3:00 PM with DLSA, Secretaries of Jharkhand.***

3. *All DLSAs to tag the handbill (copy enclosed) with all the letters to the legal services Lawyers regarding their appointment for providing free legal services/information to legal services seeker.*

Your goodselves are humbly requested to ensure implementation of these directions/guidelines.

Thanking You.

Yours faithfully
18/8/18
(Arun Kumar Rai)
Member Secretary

Encl: As above

Scanned by CamScanner

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

महत्वपूर्ण संदेश

1. विधिक सेवा जिन्हे मिली है, वह निम्नलिखित सभी सेवाएं मुफ्त में प्राप्त करता है।

   (i) पैनल अधिवक्ता प्राप्त करना, जो न्यायालय में मामला दायर करे या पूर्व से दाखिल मामले में पैरवी करे।

   (ii) कोर्ट फी माफ।

   (iii) टाइपिंग, फोटोकॉपी आदि।

   (iv) दस्तावेजों का नकल निकलवाना आदि।

   (v) केस में कोई भी आवेदन दाखिल करने।

   (vi) मुकदमा के बाबत हर तरह का खर्च।

2. विधिक सेवा जिन्हे मिलती है, उनके तरफ से मुकदमा करने/मुकदमा लड़ने का सारा खर्च जिला विधिक सेवा प्राधिकार/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति वहन करती है।

3. विधिक सेवा जिन्हे मिली है, उन्हें पैनल अधिवक्ता को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है।

4. विधिक सेवा जिन्हे मिली है, उन्हें अपने मुकदमे के बाबत एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है।

5. विधिक सेवा जिन्हे मिली है, उन्हें उच्चतर न्यायालयों में अपील, रिविजन, रिट आदि करने के लिए विधिक सहायता दी जाती है।

6. विधिक सहायता जिन्हे मिली है, उन्हे मुकदमे में पारित आदेश,आर्डरशीट आदि का सत्यापित प्रति मुफ्त में मिलती है। यह देना जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कर्तव्य है।

7. अगर जिला विधिक सेवा प्राधिकार/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का कर्मचारी अथवा पैनल अधिवक्ता पैसा मांगते हैं तो कृपया जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव (मोबाईल नं0.....)/अध्यक्ष (लैंडलाईन नं0.....), राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव (मोबाईल नं0-8986601912), उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव (मोबाईल नं0-9431100488) को अविलंब सूचित करें।

8. जहां तक संभव होगा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति पैनल अधिवक्ता को बदल सकते हैं अगर विधिक सेवा प्राप्त व्यक्ति उनकी सेवा से असंतुष्ट है।

***

Scanned by CamScanner